



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पोखरी



E Mail :- eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 313 / 15 सी.
सेवा में,

दिनांक 14/02/2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर ।

विषय:- जनपद- चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में उडामाण्डा से तल्ला बिनगढ़- खुनीगाड-कुमेडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.51 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/41083/2019)

सन्दर्भ:- भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/१०५/२०२१/एफ०सी० दिनांक 16.02.2024 ।

महोदय,
उपरोक्त विषयक मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र सं० 8बी/ यू०सी०पी०/ ०६/१०५/२०२१/एफ०सी० दिनांक 16.02.2024 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रतिपूरक वनीकरण: (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.02 सिविल सोयम भूमि ग्राम खल्यु खसरा संख्या 1,2,54,56 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.02 सिविल सोयम भूमि ग्राम खल्यु खसरा संख्या 1,2,54,56 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रू० 5723277.00 की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से खाता सं० 150896141083431 में जमा की जा चुकी है। (संलग्न:-1)
	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ.सी.ए., 1980 & 2023 की Guideline के Chapter-2 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 5.02 है० सिविल सोयम भूमि जिलाधिकारी चमोली द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। (संलग्न:-2)

42

	(ग)प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य: (क) इस संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008, एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2)दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.51 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त मान्य है।
	(ख)विशेषज्ञ समिति के रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0बी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्न:-3)
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 215 वृक्षों एवं 36 सपलिंग्स से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित और परिवर्तित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामांतरित गैर-वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 के प्रासंगिक धारा (ओं) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण-।। / अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त मान्य है।
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का मलबा निस्तारण नहीं किया जाएगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	शर्त मान्य है। (संलग्न:-4)
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्याय 11 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की	शर्त मान्य है।

2.1

	प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	
8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण- II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग कार्य रोक देगा।	शर्त मान्य है।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल(http://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि ई-पोर्टल(http://parivesh-nic-in/) वन विभाग के पक्ष में डी0बी0टी0 के माध्यम से खाता सं0 150896141083431 में जमा की जा चुकी है।(संलग्न:- 1 के अनुसार)
11	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh-nic-in/) पर अपलोड कर दी जायेगी।
	(ख) राज्य वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि सौंपने के पश्चात् क्षेत्र में शर्तों की सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन वचन पत्र के रूप में अनुपालन चरण- II अनुमोदन से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
1	वन-भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान सामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मान्य है।
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	शर्त मान्य है।
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक /राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीयवन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहाँ भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
6	वैकल्पिक/ प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में पाँचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व	शर्त मान्य है।

Handwritten signature

	वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	शर्त मान्य है।
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
9	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
10	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त मान्य है।
12	संबंधित वन मंडल के अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हों।	शर्त मान्य है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।	शर्त मान्य है।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहाँ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।	शर्त मान्य है।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामाग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा के नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित	शर्त मान्य है।

Handwritten signature

	करने का कार्य किया जाएगा। मलवा को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थयीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
21	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	शर्त मान्य है।
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	शर्त मान्य है।

अतः उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर अपलोड कर वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 04 नं0

0/c

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
पोखरी।

पत्रांक 313 /15 सी.

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, 7वाँ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

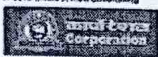
प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता-प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पोखरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

0/c

अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
पोखरी।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-02-2025

Agency Name.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT POKHARI
Application No.	6141083431
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/105/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive engineer construction division public works department pokhari Chamoli
Amount(In Rs)	5723277/-

Amount in Words : Fifty-Seven Lakh Twenty-Three Thousand Two Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896141083431 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-02-2025

Agency Name.	OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER CONSTRUCTION DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT POKHARI
Application No.	6141083431
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/105/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	office of the executive engineer construction division public works department pokhari Chamoli
Amount(In Rs)	5723277/-

Amount in Words : Fifty-Seven Lakh Twenty-Three Thousand Two Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896141083431 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
मोखरी (चमोली)

E-mail

!! आदेश !!

जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड पोखरी में उडामाण्डा से तल्ला विनगढ़-खुनीगाड़-कुमेड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 02.51 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 05.02 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या-8 बी/यू0सी0पी0/06/105/2021/एफ0सी0/1468 दिनांक 19.02.2024 में प्राविधानित शर्तों के अनुसार उप जिलाधिकारी पोखरी के पत्र संख्या-597/र0का0-क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/2024-2025 दिनांक 20.05.2024 के अनुक्रम में विकास खण्ड पोखरी में उडामाण्डा से तल्ला विनगढ़-खुनीगाड़-कुमेड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली 02.51 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम खाल्यू लगगा सिनाउ, पटवारी क्षेत्र देवर, तहसील पोखरी, जनपद चमोली के ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या-08 के खसरा संख्या 01 रकबा 1.718 हेक्टेयर, खसरा संख्या-02 रकबा 0.719 हेक्टेयर, खसरा संख्या-54 रकबा 2.007 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या-56 रकबा 1.938 म0 0.576 हेक्टेयर कुल 05.020 हेक्टेयर भूमि, श्रेणी-10 (04) अन्य कारणों से अकृषिक भूमि भीटा, भूमि को प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के आलोक में वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्थान: गोपेश्वर,

दिनांक: जून 2024,

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली

संख्या- 4474/छब्बीस-29 (2023-2024) दिनांक: गोपेश्वर: तददिनांक हस्ताक्षरित, प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।
- 02- प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 03- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 04- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
- 05- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 06- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार पोखरी।
- 07- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ/कैदारनाथ/अलकन्दा वन प्रभाग गोपेश्वर।
- 08- प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
- 09- सहायक भूलेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग पोखरी।
- 11- कार्यालय प्रति।

Signed by Himanshu

Khurana (हिमांशु खुराना)

Date: 07-06-2024 15:18:37

जिलाधिकारी,
चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)